

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरुण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 168/2019

अपीलाण्ड्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- सुमेर सिंह पुत्र खुशाल सिंह 2- उदय सिंह पुत्र खुशाल सिंह 3- कान सिंह पुत्र खुशाल सिंह 4- अर्जुन सिंह पुत्र खुशाल सिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम कांकेलाव तहसील व जिला जोधपुर		1- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर 2- जालाराम पुत्र सुखराम 3- पोकरराम पुत्र लाखाराम 4- मुमली पुत्री सुखराम 5- गंवरी पत्नी सुखराम 6- भेंपाराम पुत्र खंगारराम 7- हाऊलाल पुत्र खंगारराम जातियान विश्‍नोई निवासीगण पीथावास तहसील व जिला जोधपुर 8- भंवरलाल पुत्र मंगलाराम जाति जाट 9- केवशराम पुत्र केसाराम 10- नारायणराम पुत्र केसाराम 11- धर्मराम पुत्र केसाराम 12- देवाराम पुत्र खीयाराम 13- ओपाराम पुत्र खीयाराम 14- सोनाराम पुत्र खीयाराम 15- श्रीराम पुत्र फगलाराम जातियान विश्वनोई निवासी पीथावास तहसील व जिला जोधपुर 16- खुशाल सिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर 17- रम्बा देवी पत्नी लिखमाराम 18- चन्द्राराम पुत्र लिखमाराम 19- डुंगरराम पुत्र लिखमाराम 20- सुरजाराम पुत्र लिखमाराम 21- मुलतानराम पुत्र लिखमाराम 22- ओमाराम पुत्र लिखमाराम 23- गंगा पुत्री लिखमाराम 24- छोटी पुत्री लिखमाराम 25- फुलीदेवी पत्नी रूपाराम 26- मोडाराम उर्फ राकेश पुत्र रूपाराम 27- मंजु पुत्री रूपाराम 28- रीना पुत्री रूपाराम जातियान नायक निवासी जालेली फौजदारां तहसील व जिला जोधपुर 29- घासीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 22-6-2018 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर केम्प कांकेलाव जोधपुर के प्रार्थना
पत्र संख्या 30/2017 (23/2017) अनवान तहसीलदार जोधपुर बनाम सुमेरसिंह,
उदयसिंह वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री उम्मेद सिंह बांवरला अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 1 की ओर से ।
- 3- श्री रमेश भादू अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2, 4 व 5 की ओर से ।
- 4- श्री जेठाराम सेन अधिवक्ता रेस्पोंड सं० 16 से 19, 21 से 28 की ओर से ।
- 5- श्री शंकर सिंह जाखड अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 15 की ओर से ।

3-
अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 23-7-2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेसपो0 संख्या 1 तहसीलदार जोधपुर ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10-8-2016 के अनुसरण में चलाये गये रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम कांकेलाव पटवार मण्डल कांकेलाव तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबरान 624, 629, 626, 628, 623, 622/1, 630, 631, 620, 621, 619, 617, 616 व 605 में से मौके पर चल रहे रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये । उक्त प्रस्ताव के सलंगन उपरोक्त खातेदारों की जमाबंदी की नकले, मौका रिपोर्ट एवं नक्शा आदि प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-6-2018 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित खसरान की भूमियों का सलंगन नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये । साथ ही तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परंतु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक खसरा नंबर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की जायेगी । साथ जिन खसरो की भूमि में किस्म गै0मु0पाल दर्ज है, उसकी किस्म परिवर्तन नहीं की जायेगी तथा सलंगन नक्शा इस आदेश का अंग समझा जायेगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलाट अधिवक्ता ने अपील भीमो में वर्णित कथनों को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया तथा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना तथा अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में विधिविरुद्ध एकतरफा आदेश पारित किया है जबकि किसी भी पक्षकार के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकार को आपत्ति प्रकट करने हेतु तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक होता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा तामिली प्रक्रिया अपनाये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने कथन किया कि मौके पर अपीलाटगण के खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 624 रकबा 29.19 बिस्वा तथा खसरा नंबर 626 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वक्त सेटलमेंट से लेकर आज तक किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर नहीं है परंतु कुछ स्वार्थी तत्वों के कहने पर तहसीलदार ने एकतरफा फर्द मौका दिनांक 9-12-2016 में अपीलाट की खातेदारी में से परम्परागत रास्ता बता दिया तथा जिसके



वकील • धर्मभोगीय बायुक्त
जोधपुर

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना विधि विरुद्ध व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

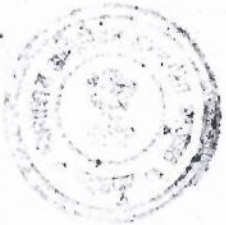
रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए उसका समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार जाधपुर ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग में आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है, ऐसे रास्तों को चिन्हित कर, रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शे में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में घोषित रास्तों के अलावा पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ते खातेदारों के खेत में आने जाने के लिए उपलब्ध है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 16 से 19, 21 से 28 की ओर से अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की तथा उनकी लिखित बहस को ही अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में उक्त रेस्पो0गण को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पो0गण की अनुपस्थिति में बिना विधिवत तामिल के जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0गण के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार का सार्वजनिक रास्ता नहीं चलता है तथा कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 17 से 10 एवं 21 से 28 के खातेदार अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं इसलिए अन्य खातेदार जोर जबरदस्ती अपनी पंहुच के कारण अवैध तरीके से हमारी खातेदारी में से रास्ता निकालने का जो आदेश पारित किया है जो विधि एवं न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 15 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्तों की समस्याओं के समाधान शिविर के तहत राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10-8-2016 के अनुसरण में ऐसी भूमियां जिन पर मौके पर कदीमी रास्ते चालू हैं परंतु उनका राजस्व रेकॉर्ड में अंकन नहीं है ऐसी भूमियों के प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है,




वकील रेस्पो0 संख्या 15 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में उन रास्तों को ही चिन्हित कर प्रस्तावित किया है जो मौके पर चालू है तथा कुछ में ग्रेवल सड़के आदि बनी हुई है उन्हीं के संबंध में आदेश पारित किया है इसलिए अपीलांतगण की उक्त अपील खारीज योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-6-2018 का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3/2/राज-6/2003/पार्ट/04/दिनांक 10-8-2016 जिसमें रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, उक्त परिपत्र में ऐसे कदीमी से चले आ रहे सार्वजनिक रास्ते, जो मौके पर चालू है परंतु उनका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया हुआ है, उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रस्ताव संबंधित पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. से तैयार कर अपनी अभिशंषा के साथ प्रेषित किये गये थे, जिन प्रस्ताव के सलंगन संबंधित खातेदारों के जमाबंदी की नकले, नक्शों की नकल, मौका रिपोर्ट आदि प्रेषित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा तथा मौका फर्द आदि का परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-6-2018 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित खसरा की भूमियों का सलंगन नजरी नक्शों में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये । साथ ही तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परंतु नक्शों में व जमाबंदी में पृथक खसरा नंबर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की जायेगी । साथ जिन खसरो की भूमि में किस्म गै0मु0पाल दर्ज है, उसकी किस्म परिवर्तन नहीं की जायेगी तथा सलंगन नक्शा इस आदेश का अंग समझा जायें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होना पाया जाता है ।



परिणामस्वरूप अपीलांत की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-6-2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23-7-2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।


(अरुण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्मानीय आयुक्त
जोधपुर